



१०/१८

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ता. 614] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1988/अश्वहायण 3, 1910
No. 614] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1988/A GRAHAYANA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

नागरिक, भौतिक, शिक्षणी, संस्कृति, विद्या, विज्ञान मन्त्रालय

(कार्यक और ग्रांथालय विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1988

प्रधिकार

को। ० शा। ० ११०(अ) केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के
कर्मों निश्चित मामले की, अर्थात्, तमिलनाडू में चीनी कारखानों से गन्ना शीरा की

बड़ी मात्राओं का परिवोधित स्पिरिट और पेय एल्कोहॉल में परिवर्तन करने के लिए अपर्याप्ति की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोप में राजस्व की भारी हानि हुई है, जून, 1979 से आगे की अवधि के दौरान निम्नलिखित राज्य में और उससे केरल राज्य को और केरल राज्य में परिवोधित स्पिरिट की बड़ी मात्राओं के और प्रतुगत मात्राओं में अधिक मात्राओं के अवैध भंगलन की, तथा उससे संबंधित अधिकारियों द्वारा आचरणों को जांच करने के लिए, एक सदस्य, अर्थात्, उडीमा उच्च न्यायालय के गवानिरूप मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. के. रे. निलकंठ बने जांच आयोग का अस्तिवशील रहना प्रबंध और आवश्यक नहीं है।

2. अन्त केन्द्रीय सरकार, आव आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) का धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा करती है कि यह अधिसूचना के राज्यपत्र में प्रकाशन की सत्रीय से उक्त आयोग अस्तित्वशील हो जाएगा और वी प्रथा के उद्देश्य आयोग के सदस्य के पद पर भी रहेगा।

[संख्या 375/11/81-ए.वी.डी. (IV)]

श्रीमती वी. वैन. विनुकत रत्नित

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 24th November, 1988

NOTIFICATION

S.O. 1100(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry consisting of a single member namely, Shri S. K. Ray, retired Chief Justice of Orissa High Court, which was appointed under the notification of Government of India in the late Minister of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 488(E) dated the 10th June, 1981, to enquire into a definite matter of public importance, namely, diversion of large quantities of sugarcane molasses from sugar factories in Tamil Nadu for conversion into rectified spirit and potable alcohol, resulting in huge loss of revenue to the State exchequer, the illegal movement during the period from June, 1979 onwards, of huge quantities of rectified spirit, and in excess of the permitted quantities, in and from the State of Tamil Nadu to and in the State of Kerala, and the alleged corrupt practice relating thereto, is no longer necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declares that the said Commission shall cease to exist and Shri S. K. Ray shall cease to hold the office of the Member of the said Commission on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[U. No. 375/11/81-AVD.IV]
SMT. B. SEN, Jt. Secy.

